into them. Hon. Members are expected to write to him. He will enquire into them. He has got an excellent vigilance arrangement with the NTC. Secondly, if my hon. friends had listened to the reply of the hon. Minister, they would not have raised these points. He has completely dealt with the Textile Policy on the NTC amalgamation scheme and he has stated that the scheme is still not implemented. It is under consideration. It is for my hon. friend, the smart, young, boy like Mr. Morarka to understand. He is failing to understand. कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब आपको जवाब दे देंगे । जो कुछ है. . (व्यवधान) . . .

श्री कमल मोरारका: आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं ? Why do you want to defend it?

SHRI A.G. KULKARNI: I will defend what is defendable; I do not defend what is undefendable.

SHRI KAMAL MORARKA: We want one assurance from the Minister that no Government land will be sold.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I raised a number of points. I gave a concrete case. I wanted to know why the Government entered into a foreign deal with a foreign country which would mean a loss of Rs. 9 crores to our country. This is not about a person or a Minister. Why should he not answer that?

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): We are discussing a Calling Attention. It is not a question-answer session. Even for questions the Ministers seek advance notice so that the Ministers can come thoroughly prepared with the information. The purpose of a Calling Attention is to call the attention of the Minister to the various aspects of a problem or situation with all of which he might be ready or he might not be ready. During the discussion various points come up and the Minister will study them and look into them. It is not always possible for the Minister to react then and there on the floor of the House in response to all the questions; he will have to get the points examined, inquired into. Therefore, we cannot convert this into a question-answer session. The Minister's answer may be satisfactory or may not be satisfactory. The idea is you draw the attention of the Minister through your points and questions to the lapses and lacunae and the Minister will study them and take necessary action. He cannot straightway react positively or negatively on the floor of the House. You have brought it to the notice of the Minister and he has taken cognizance of the points raised (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Nothing will go on record.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The Chair has already called the next item. . . . (*Interruptions*) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : जो विषय यहां उठाय गया उसके संबंध में श्री रामनिवास मिर्धा जी ने उत्तर दिया है, और बातों के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मेरे पास लिखकर आयेगा तो मैं सदस्यों को सूचित कर दूंगा, कालिंग अटेंशन मोशन अब खत्म हो चुका है । दूसरा जो विषय है वह भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक का है । अब हम उसको लेते हैं । श्री कैलाशपति मिश्र ।

(*At this stage some hon. Members left the Chamber.*)

PREVENTION O FCORRUPTION BILL 1987—Contd.

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक अभी तक देश में अनेक बार आ चुका है । 1947 में संशोधन विधेयक आया था, फिर 1964 में आया, फिर 1987 में आया और

[श्री कैलाश पति मिश्र]

इस समय 1988 में हम इसे पारित करने जा रहे हैं। मैं सरकार से एक घटना का उल्लेख करके जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक से भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा।

महोदय, देश के अंदर एक बड़ा प्रसिद्ध कारखाना है। एक तो बिहार में जमशेदपुर में टाटानगर में पड़ा हुआ है। इसी की कई कन्सर्न देश के अन्य भागों में काम कर रही हैं। एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में उस फर्म की सम्पदा इस गति से बढ़ती जा रही है कि एक तरफ देश का आर्थिक विकास पर-केपिटा इन्कम की कितनी वृद्धि हो रही है इसका यदि हिसाब लगाये और टाटा कम्पनी का हिसाब लगाये तो कहीं कोई संतुलन नहीं दिखाई देता है। जमशेदपुर में लोहा बनाने की फैक्टरी लगी है। लोहे के कच्चे सामान की को लरीज अनेक स्थानों पर लगी हुई है। बासबानी और गोआमुंडा थे दो लोहे की खदानें बड़ी प्रसिद्ध हैं। उन खादानों से इस काम के लायक कच्चा माल टाटा कारखाने में आता है। जहां खादानें हैं वहां पर फेरो मैंगनीज कारखाना लगा हुआ है उसके अंदर संशोधन होकर तब वह कच्चा तत्व, कच्चा सामान टाटा फैक्टरी में आता है जिससे इस्पात बनता है। लेकिन फेरो मैंगनीज में एक विशेष प्रकार का कोयला लगता है जिससे वह सामान तैयार होता है उसके लिए जमशेदपुर में टाटा फैक्टरी के अन्तर्गत प्लांट लगा हुआ है। कोयले की खादान से पहले कोयला यहां निकलता है। उसको साफ किया जाता है। "पर्ल कोक और नोट कोक" के रूप में तैयार होता है तब बासबानी और गोआमुंडी मे फेरो मैंगनीज में काम करने के लिए भेजा जाता है। बीच में रेलवे का आदित्यपुर यार्ड बना हुआ है। टाटा कम्पनी उन रेलवे वालों से वैगन बुक कराती है अपने इस काम के लिए बासबानी और गोआमुंडी से रेलवे वैगन्स जमशेदपुर कारखाने के अंदर आते हैं और जमशेदपुर करखाने से सामान ले करके बासबानी और गोआमुंडी में रेलवे वैगन जाते हैं। आदित्यपुर में जो रेलवे यार्ड बना हुआ है। उसका डिवीजनल सेन्टर चक्रधर पुर में बना हुआ है। नियम यह है कि कि रेलवे में जो सामान बुक होता है उसकी एन्टरी होनी चाहिए और आर.आर. होनी चाहिए और दोनों हिसाब से भाड़ा मिलना चाहिये। पता नहीं यह कब से चल रहा है। रेलवे के डिब्बे दोनों तरफ से भरकर जाते हैं और भर कर आते हैं लेकिन लगातार रेलवे के डिब्बे रिकार्ड में खाली दिखाये जा रहे हैं। इसमें रेलवे के अधिकारी शामिल हैं, फैक्टरी के अधिकारी शामिल हैं, विजिलेंस के अधिकारी भी हैं। कहीं इसके ऊपर चैक नहीं होता सामान ढोया जा रहा है। उसका आधे से भी कम सामान रेलवे वैगन में बुकिंग होते हुए दिखायी जाती है। संयोग से 1974 में एक ईमानदार अफसर वहां पर आये। विजिलेंस अफसर थे उन्होंने उसकी छानबीन शुरु कर दी। छानबीन शुरु करने के बाद पता चला कि भारी घोटाला है। जैसे ही जांच शुरु हुई तुरन्त ऊपर से पदाधिकारियों से मिल कर उस अफसर का वहां से ट्रांसफर करा दिया गया। स्वराष्ट्र मंत्री जी केवल रेलवे का सवाल नहीं है देश के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और सरकार किन-किन लोगों के हाथ में खेल रही है यह आपको पता नहीं है। लेकिन केवल तीन साल की जांच हुई। 73-74-75 की जांच हुई तो पता लगा कि टाटा कम्पनी के टिस्को के मालिक ने 50 करोड़ों रुपये से अधिक का घाटा केवल रेलवे को दे दिया। यानी 50 करोड़ रुपयों से अधिक का घाटा। मैं केवल एक साल की रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

Number of wagons received and booked.

टाटा से केवल 13 वैगन्स बुक किये जाते हैं और वासवाई में वगन्स

प्राप्त होते हैं 27 । बुक किये जाते हैं 14 और प्राप्त होते हैं 24 । बुक किये जाते हैं 12 और प्राप्त होते हैं 23 । 30 प्राप्त होते हैं और बुक होते हैं निल । 31 प्राप्त होते हैं और बुक होते हैं निल । 12 बुक होते हैं और प्राप्त होते हैं 23 । बुक होते हैं निल और प्राप्त होते हैं 53 । प्राप्त होते हैं 66 और बुक होते निल । प्राप्त होते है 120 और बुक होते हैं निल और इसी प्रकार से बुक होते हैं निल और प्राप्त होते 77 । यह सन् 1977 का जनवरी से लेकर नवम्बर तक का रिकार्ड है । अगर आप इन तीन वर्षों की छानबीन करें तो आपको पता चलेगा कि 50 करोड़ का घाटा रेलवे को हुआ हैं । यह रुपया रेलवे को प्राप्त होना चाहिये था, यह उसको प्राप्त नहीं हुआ है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह घाटा केवल रेलवे को ही नहीं हुआ है बल्कि अन्य विभागों को भी हुआ है । अगर वुकिंग आधा दिखायें या कम दिखायें तो उसके अनुसार प्रोडक्सन भी कम दिखाया जाता है और अगर प्रोडक्सन आधा दिखाया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है । उसका आप अन्दाजा लगाइये। भारत सरकार को जितनी एक्साइज ड्यूटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलती है, जितना इनकम टैक्स मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है । सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा कम्पनी के अन्दर जिनके शेयर्स होते हैं उनका जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है ।

महोदय, इस मामले में केस चलाने के लिए अनुसंशा की गई थी और उसका पूरा-पूरा रिकार्ड भी हमारे पास है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अगर वे कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हैं, सरकार टाटा के विरुद्ध कुछ साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है तो सर्टिफाइड रिकार्ड हमारे हाथ में है, आप उसकी छानबीन कराइये । इतना बड़ा स्केन्डल एक प्राइवेट फर्म ने किया है । यह घोटाला करोड़ों और अरबों रुपयों तक पहुंच गया है । अरबों रुपये भारत सरकार के खजाने में नहीं आ रहे हैं, राज्य सरकार के खजाने मे जो रुपया आना चाहिए था वह नहीं आ रहा है । सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा चाहे रेलवे के हों या बिहार सरकार के हों या केन्द्रीय सरकार के हों, लाख, दो लाख, पांच लाख और दस लाख रुपये जगह पर पहुंचा दिये जाते हैं । इस प्रकार से सारा का सारा केन्द्रीय सरकार का और राज्य सरकार का भट्टा बैठ गया है । इतना भयंकर घोटाला देश के अन्दर हो रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई है । मैंने प्रमाण के साथ केवल एक नमूना आपके सामने रखा है । इस संबंध में कार्यवाही करने का आदेश होने के वाद भी और कोर्ट का आदेश होने के बाद भी टाटा के मालिकों और अन्य अफसरों के खिलाफ कार्यवाही के नाम पर निलम्बन तक नहीं हुआ है । अन्य रेलवे के अफसरों के खिलाफ नौ-नौ मुकदमें चलाने की अनुसंशा हुई थी उनमें से रेलवे बोर्ड ने एक पर भी मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है । अगर ऐसा खेल खेलते रहने की इजाजत होती रही तो आप करप्शन प्रिवेंशन के एक नहीं अनेक एमेंडमेंट लाते रहिए, इनसे कोई लाभ मिलने वाला नही है और सरकार की ऐसी ही मंशा रही तो कभी भी करप्शन इस देश से समाप्त नहीं हो सकता है । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हू कि जब वे अपना उत्तर द तो यह कह कर इस मामले को न टाल दें कि यह रेलवे का मामला है । मैं समझता हुं कि यह बात भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का मामला है, यह होम मिनिस्ट्री का मामला है, यह विहार सरकार और राज्य सरकार का मामला है । इसमें अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है, दस्तावेज इसके प्रमाण हैं । मैं जानना चाहता हू कि इतने दस्तावेज होने के बाद सरकार इस संबंध में कौन-सा-कदम उठाने जा रही है ?

[श्री कैलाश पति मिश्र]

सरकार किस प्रकार से यह करने जा रही है ? अगर करने का संकल्प नहीं हो, करने की मशा नहीं हो, करने का साहस नही हो और मुट्ठीभर उद्योगतियों के हाथ में सरकार खेलती रहे, भ्रष्ट उद्योगपतियों के हाथ में सरकार खेलती रहे और सरकार का पूरा तंत्र अगर उनके अनुसार खेलता रहे तो एक बार नही बल्कि सौ बार भी अमेंडमट पास करा लीजिये उससे कुछ निकलने वाला नहीं है । पिछले तीन वर्षों में 50 करोड़ रुपयों का टाटा का घोटाले का मैंने जिक्र किया और जिस रास्ते से घोटाले चल रहे थे वह रास्ता आज भी जारी है, रुका नहीं है । अन-बुकड रेलवे वैगन लगातार अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर काम कर रहे है । आज भी अगर वहां छापा मारा जाये, जांच की जाय तो ये सारे तथ्य, किसी को भी चौंकाने वाले तथ्य, आपके सामने आकर खड़े हो जायेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : कृपया समाप्त करें ।

श्री कैलाश पति मिश्र : अगर हिम्मत नहीं है तो आप सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे रहने के लिये तैयार है तो ऐसे अमेंडमेंट्स से कुछ होने वाला नहीं है । धन्यवाद ।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir the dawn of independence and democracy threw such new challenges to the Government which the alien rulers never addressed themselves to and the variety and magnitude of the task ahead obviously called for a vast administrative and implementation machinery. To begin with, the duties were discharged with a sense of sincerity and commitment. But with the governmental activities progressively spreading and covering new fields, here has been a perceptible decline in he standards of integrity and efficiency of our public administration. To achieve he goal of democratic socialism, the Government has been formulating well-considered schemes. But the results have not been up to the expectations because there has been a leakage of funds somewhere in the process of implementation. Today funds meant for important developmental activities and projects are misappropriated and the public property pilfered without any compunction. It is a sad reflection on our system that corruption has permeated to all levels of public administration. Fixed rates of bribery have come o be known and accepted for job recruitment, for grant of routine licences, for sanction of building plans, for sanction of water, electricity and sewer connections for grant of Scheduled Castes and Scheduled Tribes or Backward Class certificates, for supply of certified copies of public documents, for allotment of dwelling units under the Housing Schemes, for obtaining loans under the self-employment schemes, for registration of property and even for railway reservation and booking. Such a list is, in fact, endless. Individuals and businessmen also, while dealing with a Government department or a public enterprise, work out their cost and profits only after taking into account what is euphemistically called a fee payable for the work done or the service provided. Sir, the all-pervading corruption that has permeated into the vitals of our systems can legitimately be described as something universally condemned, helplessly lived with and willingly given or ruthlessly extracted.

To root out corruption, the Rajiv Gandhi Government has launched a relentless war. The latest step in this direction is the introduction of this Prevention of Corruption Bill, 1987, a consolidated Bill seeking to replace the existing law on the subject which was spread over a number of enactments and proved to be inadequate in fighting the menace effectively.

A distinctive feature of this Bill, Sir, is the widening of the definition of the term 'public servant', and in my opinion this should also help cleanse the public life and eliminate any chance of corrupt official seeking and enjoying political

patronage. Co-operative societies play a very significant role, particularly in rural life. But rampant corruption in their functioning has emaciated the co-operative movement. Today, the academic life of our Universities and colleges is also vitiated. Some unscrupulous elements for personal gains do not hesitate to inflict a crippling blow to the seats of learning. Cases are not wanting where examination papers are leaked, where unfair means are resorted to en masse and awards are altered for consideration. It is gratifying that the Government has taken a serious view of this malady and extended the provisions of the proposed new legislation to the co-operative societies ,as well as to all those persons who serve in the Universities and are associated with the holding of examinations. (*Time bell rings*) Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): There are 11 speakers from your Party and the time allotted is only 51 minutes. Hardly it comes to five minutes and you have already taken...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Then, I don't think I will be able to speak...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Let him continue. Sir.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, seeing the gravity of the prevailing situation, the Government has risen to the occasion to eliminate corruption with a heavy hand. Laying down of minimum sentence of imprisonment for any proven offence of corruption should serve as a deterrent to any delinquent public servant who indulges in corrupt practices And the Government has also rightly taken into account the prevailing situation where some people habitually resort to corrupt prctices. Enumerating various cases of such criminal minsconduct in Clause 13 of the Bill, an enhanced minimum sentence of imprisonment for one year and extendable to seven years has been appropriately provided for such offenders.

Sir, for expeditious disposal of cases, steps are postulated to hold trial of an offence on day-to-day basis and the formalities of committal proceedings are sought to be done away with. Power is also conferred to try certain cases summarily. Barring of writ petitions or grant of stay against interlocutory orders will also check the guilty from unduly prolonging the proceedings and from evading action. We have seen that the guilty often thwart the process of law by resorting to hyper-technicalities. Such tendencies are now sought to be checked by the provisions of the new Bill. This will inspire a sense of confidence in the public mind that Government means business, and means to fight corruption head on with firm determination. Such determination of the Government is also manifest from a provision of the Bill which postulates that for trial of offences under the new enactment special judges would be appointed. I do hope that the special judges to be appointed for this purpose would not be from amongst the sessions judges who are already, overloaded with the existing work.

Sir, another salient feature of the new Bill is that a person who is expecting to be a public servant and commits an act forbidden by this law would also attract its penal consequences. However, in my opinion. Explanation (a) added to clause 7 can cause some difficulty in a given case. For instance, a person may just happen to appear in an examination or an interview for a service, and thereafter obtain a gratification by making someone belive that he is about to be in office. If apprehended and convicted, he could well argue that the provisions of this clause are not attracted in his case because he did not expect to be in service. Sir, in view of this I feel that the touchstone for the applicability of the provisions of the new Bill should be the action of 'holding out' by the accused person and not his 'personal' belief. In

[Shri Pawan Kumar Bansal]

view of this I feel that this Explanation (a) needs to be omitted from the provisions of the Bill.

Also, Sir, the word "erroneously" occurring in Explanation (e) to this clause, I feel, should be deleted because this can also sometimes lead to a difficulty in the interpretation of the clause.

Sir, the resolute will of the Government to root out corruption is again clear from clauses 8 and 9 of the Bill which spread the net to cover those individuals also who take gratification as a consideration for inducing by corrupt or illegal means or by personal influence any public servant for the commission or omission of certain acts. This is a welcome povision. But I think the marginal note to clause 8 remains erroneous even after the amendment made thereto, because the words "by corrupt or illegal means" refer to an individual's act of influencing a public servant and not the act of taking gratification personally.

Sir, clause 23 of the Bill rightly says that in the case of misappropriation of any property entrusted to a public servant each particular item or the exact date of entrustment need not be described in the charge. This will definitely help curb corruption on the part of those public servants who often misappropriate the public property entrusted to them. But here I feel that the proviso to this clause which says that the time included between the first and the last of such dates shall not exceed one year, would in some cases nullify the effect of the main provision. For instance, the entrustment of some property to a public servant may remain for three years and it may be only at the end of that period that the fact of his misappropriating the property comes to notice. In such a situation the accused should not be able to avail of this embargo on legal action and avoid penal consequences.

4.00 P.M.

It is common knowledge that the poor victims of avarice of the unscrupulous and corrupt officials, or even their subordinates, rarely have the courage to report an offence to the vigilance authorities for fear of reprisals from the accused who are often influential persons. So, to make the law work, it is imperative that we devise a procedure, other than the hackneyed one, of using a decoy witness to lay a trap and apprehend the accused red-handed accepting the phenolphthalein-treated currency notes. This may not be dispensable outrightly, I agree, but it definitely calls for some innovative improvement. In any case, to inspire confidence and to check corruption in future, the Government would do well to inquire into the assets of those senior officers who have in the past held important but corruption-prone positions. Action against those at the top will have salutary effect right up to the bottom. However, I must hasten to add here that those with known good reputation must not be harassed under any circumstance whatever and we must convey the message that it pays to be honest.

We have often seen that anti-corruption laws do not necessarily wipe out the evil. On the contrary, the incidence and quantum of corruption or the rate of bribe is directly proportional to the risk involved. So, while I welcome the present Bill which demonstrates, as I said, the Government's keenness to intensify its fight against corruption by treating it as a social crime, I do take this opportunity to express the hope that steps would be taken not only to punish the guilty but also to create an environment that discourages people from taking or giving bribes. In this direction, rules of procedure will have to be simplified and delay in disposal of the files in various offices viewed seriously and action taken against those who delay the disposal of the files and adopt dilatory tactics. Also the points of contact between the officials and the public have to be minimised so that any possibility of malpractice creeping in is ruled out completely. The system of inviting sealed tenders also needs to be given up in favour of open bidding to eliminate manipulation by the conniving officials.

To conclude, I would say that besides the enactment of stringent laws, a continuous study has to go on into the causes, the points and forms of corruption, and means have to be devised to fight and overcome those with a strong will. Only then the crusade against the social evil will acquire any meaning and achieve success. Otherwise, the laws would remain sterile on the Statute book and invite only contempt from the corrupt.

With these words, I support the Bill.

श्री ईशदत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा में भाग लेने का आपने जो अवसर दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, यह जो नया विधेयक इस माननीय सदन में लाया गया है मेरी इससे कोई असहमति नहीं है, लेकिन निराशा है क्योंकि संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1947 में "प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट" बनाया गया और फिर 1952 में "क्रिमिनल (अमेंडमेंट) एक्ट" पास किया गया और धारा 161 से 165-ए, भारतीय दण्ड विधान में यह प्रावधान किया गया । इस तरह के अपराध पर कंट्रोल करने के लिए या ऐसे अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई । अब 11-5-1987 को माननीय चिदम्बरम् साहब ने यह बिल पेश किया । मान्यवर, निराशा इसलिए हो रही है, यद्यपि मेरी असहमति नही है, परन्तु निराशा इसलिए हो रही है क्योंकि यह भ्रष्टाचार इस सरकार का और इस सरकार के कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है । इतने कानून बने इस देश में और कानून है भी, लेकिन यह कानून इतने कमजोर हो गए कि किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ने में या किसी भ्रष्टाचार करने वाले को दण्डित करने में वैसे कम नहीं हैं, लेकिन इन कानूनों को जो अमल में मशीनरी लाती है, वो हमारी मौजूदा सरकार है, यह कमजोर है । इसी के परिणाम में मान्यवर, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है । भ्रष्टाचार का संबंध इस सरकार से और इस सरकार के कर्मचारियों से चोली-दामन की तरह हो गया है । मुझे तो लगता है कि सरकार को इससे मोह हो गया है क्योंकि इस देश में जो कानून अब तक बने या मौजूद हैं, अगर इन पर, सरकार कड़ाई से अमल करती , अगर कड़ाई से पालन करती तो भ्रष्टाचार, मैं समझता हूं, समाप्त तो नही हो जाता, लेकिन कम जरूर हो जाता ।

मान्यवर, सरकार का रवैया क्या है । इनको पर्याप्त बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला सत्ता पक्ष में के लोगों को, लेकिन मैं कहूंगा, यह सरकार अस्थिर सरकार है । इस सरकार में मुख्यमंत्री तो प्रतिदिन कपड़े की तरह बदले जा रहे हैं, जैसे सुबह कोई कपड़ा पहना और शाम को दूसरा पहन लीजिए और भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण यह भी हो रहा है । अभी मान्यवर, इसी माननीय सदन के माननीय सदस्य थे, अब भी संभवतः हैं, श्री नारायण दत्त तिवारी जी, वे लंदन गए । अभी लंदन में उनका बिस्तरा खुला भी नहीं था कि यहां से आर्डर गए--वापस आइए । मैं समझता हूं, वे अभी लंदन और दिल्ली के बीच में ही था कि आधी रात की बेला में लखनऊ में उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया । मान्यवर, महाराष्ट्र का भी किस्सा इसी तरह का हुआ । मैं समझता हूं कि यह इस देश में पहली घटना हुई होगी कि रात को 12 बजे विधायक-मंडल की बैठक हो रही है नेता चुनने के लिए और दूसरे दिन भोर में लखनऊ और महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कराई जाती है चीफ मिनिस्टर को । इसी तरह यहां भी ताश के पत्ते की तरह मंत्रिमंडल में हेरफेर कर दिया गया कि योजना भवन से शास्त्री-भवन में बैठाया गया ।

अब मान्यवर, इसका परिणाम क्या होता है, इसके लिए मैं आपको उत्तर-प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, हमारे माननीय वीर बहादुर सिंह जी वहां मुख्यमंत्री थे । सारी की सारी पोस्टों पर उन्होंने आदमी बैठाए, अब वह

[श्री ईशदत्त यादव]

एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से बैठाए या जैसे भी बैठाए... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : (मध्य प्रदेश) : मुख्यमंत्री के अधिकार के बतौर बैठाए ।

श्री ईशदत्त यादव : अब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी वहां गए, रोज सुबह उठिए, अखबार में लंबी लिस्ट देखिए आई.ए.एस. आफीसर्स की, आई.पी.एस. आफीसर्स की । तो यह आज का चरित्र है, मान्यवर, और यह जो सरकार है, यह अस्थिर हो गई है । इसका कारण यह है कि जब रोज ताश के पत्ते की तरह और कपड़े की तरह लोग बदले जाएंगे और वह मनमाने ढंग से काम करेगा । अभी कल इसी बिल पर सत्ता पक्ष के श्री पशुपति नाथ जी बोल रहे थे । मुझे उनकी बात पसन्द आई । उन्होंने लेखपाल से लेकर बडे-बड़े अधिकारियों तक का वर्णन किया कि सब का एक दूसरे से लिंक बंधा है । स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे नेता थे वे बराबर कहते थे कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर को नही जाता, वह टाप टू बाटम आता है । अगर हमारे मंत्री और बड़े अधिकारी ईमानदार हों तो क्रमशः उनके नीचे के कर्मचारी और अधिकारी ईमानदार होते चले जाएंगे । ऐसा नहीं है कि अगर सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस या कलेक्टर ईमानदार है तो उसके नीचे काम करनेवाला एस.डी.ओ. या दरोगा घूस लेगा । आज भ्रष्टाचार कहां नही है? आज कोई भी कागज घूस दिए बिना चलता नहीं है । चाहे आप ब्लाक स्तर की बात ले लें, तहसील या जिला स्तर की बात ले लें घूस दिए बिना काम नही बनता है । अब तो लखनऊ, पटना और हर जगह के सचिवालय में भी यही स्थिति हो गयी है । इस तरह से यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में एकदम असमर्थ हो गयी है । मान्यवर, जिलों में विजिलेंस इंस्पेक्टर्स रखे गए हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह एक वर्ष के आंकड़े बता दें कि जिलों में जो विजिलेंस इंस्पेक्टर्स पोस्ट किए गए हैं, उन्होंने कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को घूस लेते हुए पकड़ा है । जिलों में विजिलेंस इंस्पेक्टर्स को आफिस दे दिए गए हैं और सुविधा दे दी गयी है । व्यवस्था की गयी है कि जिस आदमी से कोई अधिकारी/कर्मचारी घूस मांग रहा है, वह उनको लिखित देता है । उसके बाद टाइम एपांट करते हैं कि फलां वक्त जाकर तुम पैसा दे देना और हम गिरफ्तार कर लेंगे । लेकिन जब वह आदमी एप्लीकेशन देकर टाइम एपांट करता है तो घूस लेने वाले आदमी को पहले सूचना हो जाती है । कौन सूचना देता है ? यह विजिलेंस इंस्पेक्टर और उस विक्टिम के बीच म बात होती है। तब फिर यह कैसे दूर होगा ? मान्यवर, भ्रष्टाचार से संबधित जो जांच होती है यह जांच भी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका संरक्षण भ्रष्टाचार करने वालों को मिला हुआ है । इस तरह से यह सरकार असमर्थ हो गयी है । मान्यवर, मैं (समय की घंटी) तो माननीय गृह राज्य मंत्री जी से केवल एक ही चीज कहूगा कि वह केवल गाजियाबाद में जांच करा लें वहां कितने आई.ए.एस. रैंक के आफिसर्स के मकान बने हुए हैं ? जब ये अधिकारी सेवा में आए थे तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है । मान्यवर मैं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बारे में जानता हूं । गाजियाबाद और नोएडा में जमीन खरीदकर मकान बनाने की होड़ लगी है । लाखों रुपयों के मकान बनते जा रहे हैं । यह पैसा कहां से आ रहा है ।

मान्यवर मैं चाहता था कि जो मंत्रीगण हैं, इन्हें भी इसकी परिधि मे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह बिल बड़ा संक्षिप्त है और इसके तीन-चार उद्देश्य ही बताए गए हैं । मैं समझता हूं कि इसमे जो पब्लिक सरवेंट की व्याख्या की गयी है और केन्द्र सरकार को भ्रष्टाचार के केसिज में स्पेशल

कोर्ट बनाने के लिए यह प्रावधान करने की बात कही गई है और इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 161 से लेकर 165 तक का जो प्रॉविजन है उसको भी इससे संबधित करने का प्रयास किया गया है । मैंने शुरू में कहा मान्यवर, और पुनरावृत्ति हो रही है कि सरकार में बैठे लोगों को भी मंत्री-मंडल के लोगों को भी इस कानून की परिधि से बाहर नहीं रखना चाहिए था । यह सब लोग जब आते मान्यवर, तब कहीं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकता है वरना भ्रष्टाचार तो इस देश का कैंसर हो गया है, भंयकर रोग हो गया है । अभी मान्यवर, इसी सदन में 65 करोड़ रुपए के बोफोर्स पर दो बार बहस हुई और ज्योत्सना लिमिटेड कम्पनी के साढ़े छः करोड़ रुपए की एक दिन बहस हुई । मान्यवर, जब इस देश में इतने बड़े-बड़े घपले होंगे तो छोटे अधिकारी जो जिले में, राज्य प्रदेश में रहते हैं, तहसील और ब्लाक में रहते हैं, उनके हौसले तो बढ़ते चले जा रहे हैं । वह उदाहरण देते हैं मान्यवर कि जब इस देश में 65 करोड़ रुपए का घपला हो सकता है, साढ़े छः करोड़ रुपए का घपला हो सकता है तो हमारा तो मामला हजार, दो हजार का चल रहा है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप कृपया समाप्त करें ।

श्री ईश दत्त यादव : : मैं समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर मैं समाप्त ही कर रहा हूं । इन्ही शब्दों के साथ मान्यवर कि आपके माध्यम से अपने गृह राज्य मंत्री माननीय चिदम्बरम् साहब से और सरकार से यह अपेक्षा करता हू कि कानून तो आपके पास बहुत हैं और फिर यह कानून भी आप पास करा ले जाएंगे, लेकिन अगर सचमुच आप चाहते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, खतम हो तो आपको इन कानूनों का, इन उपबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा वरना इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है, आप लोग भले ही समाप्त हो जाएं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्री हरि सिंह जी ।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी आज इस सदन में प्रिवेंशन आफ करप्शन बिल 187 पर चर्चा चल रही है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने और उसका निवारण करने के लिए यह बिल इतने विस्तृत रुपये से लाई है । भ्रष्टाचार की जो शिकायतें चली आ रही थी और भ्रष्टाचार जो सरकारी कर्मचारियों में शुरू हुआ वह 1771 क्लाइव के वक्त से शुरू हुआ और वह तब से बराबर चला आ रहा है । हमारी कांग्रेस सरकार ने वक्त-वक्त पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कानून बनाए लेकिन कानून से बच निकलने वाले लोग अपनी तरकीब से ऐसी चीजें निकाल लेते थे कि बुरे से बुरा भ्रष्टाचार करने के बाद भी भ्रष्टाचार से बच निकलते थे । कानून के हाथ बड़े मजबूत और लम्बे होते है लेकिन जो चतुर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं वे अक्सर कानून की पकड़ से बच जाते हैं । तो मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस बार जो वह बिल लाई है, भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून बनेगा इसमें जो सारी कमिया और खामिया थी उनको दूर कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि इसके लागू हो जाने के बाद भ्रष्टाचार को मिटाने में बहुत सफलता मिलेगी, उस पर करारी चोट पड़ेगी और पब्लिक में जो आम जनता है, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनमें साहस जागेगा कि अब इस देश में भ्रष्टाचार मिटेगा । इस कानून के तहत स्पेशल जज मुकर्रर करने का प्रावधान रखा गया है । स्टेट सरकार को भी केन्द्र सरकार को भी भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको सीमित-रली तय करने का भी इसमें प्रावधान है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो यकीन दिलाये, भरोसा दिलाये, जानकारी देगा उसको हम थोड़ी सी इस कानून के मातहत रियायत भी दे सकते हैं क्योंकि बड़े चोर को पकड़ने के लिये कभी-कभी छोटे भ्रष्टाचारी को कुछ मुलामियत बरतनी पड़ती है इसलिये कि जो बड़ी मछली है

[श्री हरि सिंह]

भ्रष्टाचार का जो वाध है उसको पकड़ने के लिये उनको कुछ मदद करनी पड़ती है। सारे प्रावधान इसमें रखे गये हैं। जैसा कि मैंने कहा हमारी सरकार के नीयत, मन, पालिसी, प्रोग्राम यह सब बड़े साफ हैं इस बात के लिये कि हिन्दुस्तान में एक कानून से बनी निर्मल सरकार चन, भ्रष्टाचार के सहारे कोई किसी को दबा न सके। यह सारी चीजें इसमें रखी गई है और इसमें एक बात और अच्छी रखी गई हैं कि जो पुलिस आफिसर हैं अगर उनको पता लगेगा कि इसमें भ्रष्टाचार है तो वह बैंकर्स की बुक को भी देख सकते हैं, उसको जाकर चैक कर सकते हैं। तो यह जो बिल है वह बहुत ही इस मामले में विस्तृत और मजबूत है कि भ्रष्टाचार की पकड़ से बच निकलना मुश्किल होगा। तो मैं कह रहा था कि हमारी सरकार की बड़ी साफ नीयत और कार्यक्रम है कि देश के अन्दर स्वच्छ और निर्मल सरकार आये।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की लाल फीताशाही के साथ ही इनकी फाइल चलती है, आगे से पीछे और पीछे से आगे चलती है। इनका रुपया लेने का जो तरीका है उस सब को रोकने के लिये उस पर चोट करने के लिये इसमें प्रावधान किया गया है।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत में पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं जो आते चले जाते हैं, पब्लिक ईमानदारी के आधार पर फिर चुनती है तो वे फिर आते हैं, लेकिन हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेट अप है, जो हमारे कर्मचारीगण हैं वे परमानेंट होते है। अगर उनमें भ्रष्टाचार घुस जाता है या नाजायज रुपया कमाने की कामना बलवती हो जाती है तो हमारा प्रजातंत्र लड़खड़ा सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुये यह जो कानून सदन में आया है यह हमारी व्यवस्था को मजबूत करेगा। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं। अखबारों में, मैगजीनों में कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां काला बाजारियों को या नाजाइज रुपया लेने वालों को सजा न दी हो। दिल्ली के बड़े-बड़े अफसर, डी.डी.ए. के बड़े बड़े अफसर या ठेकेदारों को पकड़ा गया है, गोदाम वालों को पकड़ा गया है, कस्टम वालों को पकड़ा गया है, इनकम टैक्स के कर्मचारियों के पास लाखों करोड़ों रुपये मिले हैं, उनको पकड़ा गया है। इस तरह से जाहिर है कि छापे एक के बाद एक पड़ते जा रहे हैं।

श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी आज नींद हराम हो गई है। इस कानून के आने के बाद उनकी नींद और हराम होगी। जो भी आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं वे इसके काबू में आयेंगे। लेकिन बार बार बोफोर्स का मामला उठाना जब कि इसका जवाब कितनी बार आ चुका है और बार बार एक झूठ को कहकर उसको सच कराना अच्छा नहीं है। इस देश के प्रबुद्ध लोग समझते हैं, जनता समझती है कि उसमें कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। सरकार ने इस बिल में समरी ट्रायल का प्रावधान किया है, जजों का प्रावधान किया है। इके साथ ही आप देखें कि भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ सख्ती की जायेगी, उनकी संपत्ति भी ले ली जायेगी, सारी चीजों को नजर में रखकर यह कानून लाया गया है। इसकी जो मंशा है वह बड़ी साफ है। इससे देश के अन्दर एक नया दौर शुरू होगा और जो कदम कदम पर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में भ्रष्टाचार हो गया है, उसको मिटायेगा। इसकी तरफ हमारी सरकार बराबर चल रही है। आप जानते हैं कि आज हमारे देश को इससे बहुत पैसे का नुकसान होता है। मेरी समझ में यह बिल बहुत अच्छा साबित होगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी बिल कितना ही मजबूत बना लिया जाय, लेकिन यदि जनता जब तक तय नहीं करेगी कि इसके लिये हमने रुपया नहीं देना है, बेइमानी से काम नहीं कराना है भले ही इसमें हमें तकलीफ हो, हम नाजाइज रुपया नहीं देंगे जब तक कोई भी कानून सफल नहीं हो सकता है। मुझे बड़ी खुशी है विस्तृत नयी चीजें लेकर आये हैं मैं इसका

समर्थन करता हू और आशा करता हूं कि यह जरूर पास होगा । जयहिन्द ।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Prevention of Corruption Bill, 1987. The Prevention of Corruption Bill was enacted in Parliament in 1947 and the Bill which has now been placed before this august House is to be considered for consolidating and amending the law relating to the Prevention of Corruption the Criminal Amendment Act 1952 and the Criminal Law Amendment Ordinance 1944 and other matters connected therewith in one enactment. This is the special feature of the Bill. Considering the various important aspects of this Bill, I support it but I would like to make a few comments. The illegal acceptance of remuneration of donation for admission and even gift for fulfilling ill-motivation is to be guarded against as corruption which is increasing and demoralising our young generation and tarnishing the image of our country. Corruption is found to be prevalent in all spheres. It has percolated from higher officials to junior officials and practically in all administrative services, it is prevalent. The poor people may be involved in corruption for their survival as we find, in case of Jean Valjin. We know the story of Jean Valgin, who for a loaf of bread which he had stolen for his nephew, for his family, was put inside the jail. So, the question of poor people does not arise in this case. Even those who are well off are practising corruption. The modern society, and affluent people are responsible for such demoralisation. However, the Government are making serious efforts to prevent corruption through Administrative Vigilance Division, under the Ministry of Personnel, secondly, the Central Vigilance Commission which is rather an independent authority and the Central Bureau of Investigation. In this context I would like to point out that unless the Government officers are honest and sincere, the efforts of the Government would be futile. I, therefore, would like to know from the hon. Minister what machinery is being evolved to investigate whether the senior officers in the top rank in the Government departments are free from corruption. The Government have not yet been able to take action against capitation fee. Sir, a provision has been made in the Bill to appoint special judges. This is without derogation of the powers of the State Government to appoint special judges and special magistrates, who would be entrusted to examine the corruption cases and to take the necessary measures. I wonder, how far this procedure will be effective as this needs full cooperation and coordination of the States and the Centre. Moreover, in the selection of judges and magistrates, the Centre and the States must be extremely cautious so that the right persons are selected because many persons go scot-free on account of the liberal attitude of the judges as they take bribes and also on account of interpretation of the legal points by courts. In this connection, it needs mention that the legislation must be very clear and it must be without any ambiguity so that the situation as already mentioned above may not arise and confuse the judgment. It is also desirable that the judges must dispose of the corruption cases within a reasonably short period, even considering the interim stay for those cases. There should be time limit for finalising the judgment. However, it has been a good gesture on the part of the Government to lay down the parameters for the courts. It has been provided in the Bill that the courts shall not provide interim stay except in certain special cases but this is not going to take care of the power of the High Court under articles 226 and 227 and this will only affect the statutory powers of the High Court under Criminal Procedure Code. It is, therefore, desirable to amend the articles 226 and 227 so that the corrupt people may not escape on benefit of doubt. Sir, I think, clause 6 is to be made more clear. Why previous sanction is necessary for prosecution ?

Is there any legal implication ? Questions are also being raised about the definition of public servants. I believe that anyone working for public utility has to be

[Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee]

considered as a public servant. And this will cover all who are working in schools, colleges, universities and such institutions, professional colleges, namely medical and engineering institutions, institutions of business management, hospitals and various other organizations rendering service to the public. What steps are to be taken to prevent corruption in these organizations? Bribes are taken even from patients for their admission in hospitals. Even for housing accommodation people are paying 'salami' which is well known Otherwise they won't get accommodations. Is it not bribe? Is it not a case of corruption? What provision has been made in this Bill regarding such corruption? Regarding the legislation which has been brought before the House today, I would like to emphasise that unless the root causes of this malady, namely, poverty, socio-economic constraints, craze for living a affluent life are wiped out, I think the legislation would be ineffective. However, in this context, the report of the Santhanam Committee which came out in 1964 needs examination and the Government are requested to act accordingly.

While concluding Sir, I would like to mention that the salient feature of the Bill is that it clarifies the definition of offences and penalties. The different clauses prescribe a minimum punishment of six months' imprisonment for various offences and one year's imprisonment in the case of criminal misconduct. I would suggest, in cases of criminal misconduct and habitual offences, more stringent punishment is necessary depending on the nature and degree of offences. And the measures taken in this connection should not touch the periphery of the problem but must go into the depth of it so as to create fear in the mind of the people who indulge in such offences. They must know that their life would be in danger if they are involved in corruption which is going to ruin the nation.

With these words, Sir, I conclude and I support the Bill. Thank you.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, I thought I would not be called today at all.

SHRI P. CHIDAMBARAM : I hope to finish this today.

SHRI A. G. KULKARNI : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for calling me. My learned colleague, Mr. Bansal has given his views on legal character of the Bill. I am supporting the Bill. But I want to know from the hon. Minister the parameters in which this Bill has been brought and whether those parameters will be sufficient to meet the condition of the corrupt practices today in the country. I agree with Madam Chatterjee who has just now spoken about corruption even in educational and medical institutions. I know the example of Maharashtra. Educational institutions have become commercial organizations to earn money by the promoters of the so-called educational institutions.

Mr. Vice-Chairman I do not want to take much time. I am sure Mr. Minister is aware of the various committees like the Santhanam Committee. Recently the National Institute of Public Administration has also dealt with the colossal problem of black money and parallel economy. What I wish to say is, the political system has produced an economy in which it is possible to make a big money. I would like to ask the Minister how, in the limited scope of this Bill, the demon of corruption is going to be crushed. I do not understand what to do in the present political system, in the present administrative system. We in the villages see right from the lowest level to the Collector's office right from morning till evening money is passed on, money has to be passed on. The history of Hindu society is such that they frowned on corruption and that is why the moral values of this continent are held very high. The moral values which have been maintained, which have been held by our people, should be maintained by us. The intellectuals, the middle-class are nursing very strong views and I think that value-based politics as we call it has to be given a high priority. Yesterday and the

day before yesterday we discussed the value-based politics and morality in the political system. But I fail to understand why no political party has upheld the value-based politics. And that is why the system is collapsing. I do not want again to dwell on the very bitter experience that we witnessed two or three days back. But what I see is that the value-based politics system has degenerated because no political party is impressing upon its workers the importance of value-based politics. At the AICC Session held at Bombay the Prime Minister appealed to the workers and he expressed his determination to put down power brokers and influence pedlars. The Prime Minister's determination to put down these anti-social elements and improve the system is the right solution to these problems. I am aware that the Bill which has been brought is aimed at improving the system. In this system, I am very sorry to say, the nexsus between the politician, the industrialist and the bureaucrat has become so thick that it looks impossible to break this system by such Bills. I do think that it requires a different approach to break this nexus between the politician, the industrialist and the bureaucrat. A friend of mine just mentioned here that the Bill applies to the cooperative organisations also. Very recently I addressed a letter to the Prime Minister pointing out that he must now put his foot down on the cooperative organisations. Cooperative organisations were supposed to be service organisations. The late Pandit Nehru used to describe the cooperative organisation as a vehicle of social change. But the cooperative organisation has been controlled and cornered by anti-social elements, by various mafia groups and they are threatening the political system at the State level. I am sorry to say in Bihar very recently the Chief Minister of Bihar instituted a criminal case and now a move is on to remove the Bihar Chief Minister. This is the strength of the cooperators. In Maharashtra sugar factories are notorious for corruption. In Gujarat, I know, the system is still working very nicely. But the day is not far off when Gujarat also would fall a prey to the manipulations of the co-operative organizations. I would like to ask the Minister, the young Minister...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): The whole co-operative system is not corrupt. There may be some people who are corrupt. So, we cannot say that all are corrupt.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): I never said that. I never said that all the co-operative organizations are corrupt. You have expressed your view. That is all right. But I never said that all are corrupt.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): In Bihar, it is a byword for corruption and he was talking about Bihar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Mr. Kulkarni, you continue.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, my friend is so much worried. But I would like to tell the House that in Maharashtra, there are many societies, co-operative societies, which have been charged by the State Govenment with floating of trusts fraudulently. They have been charged not only with floating trusts fraudulently, but also with amassing of money, and, on the floor of the Assembly, it was stated that a co-operative sugar factory had on hand Rs. 67 lakhs. Mr. Minister, would you take courage to examine how these co-operative organizations, which are supposed to be service organizations, have become mafia organizations just like the gangs of smugglers and such other people?

Mr. Vice-Chairman, Sir, the politics of necessity involves the departure from principles and values and in this respect the co-operative organizations are more important. I quoted the Prime Minister's address at the Bombay AICC(I) session. What kind of a situation we are in today? Even the CBI, IB and other organizations which are expected to be the vigilance wings of the Government, which are expected to be the eyes of the Government are also lacking in some respects. I would like to tell one thing here. The grip of the industrialists on the bureaucracy has gone to such a length—I can quote very many instances—that there are some bureaucrats who have been brought to the Central

[Shri A. S. Kulkarni)

Ministries because some industrialists wanted to get help through them. I can quote examples. But I do not want to do so because it is not the practice to take the names of persons here. But I can say that some Secretaries in the Government are in the grip, are in the clutches, of the industrialists and they are being patronised by the politicians of various hues. But it is not a question of this party or that party. It is a general phenomenon. That is why I am against the system which is introducing this sort of corruption.

Sir, there are many instances which the Finance Minister himself quoted like Customs duty evasion, ante-dating of letters of credit, etc. The reports are already with the CBI. But the CBI, because of the influence of the industrialists, is not forwarding those reports to the Home Ministry for further action.

Sir, there are various cases which were mentioned here and I do not want to go into them. They are about foreign exchange violations. In this, Sir, some industrialists were also involved. I would like to request the Prime Minister to bring about a change in the system with the help of young Ministers like you to who are very highly educated. We, at the fag end of our life, cannot change the system. Please bring about a change in the system whereby our old values of morality, would be upheld in this country. And, for this purpose, I would like to request you to take action against those politicians, without fear or favour, who indulge in acts of corruption . (*Time bell rings*)... Mr. Vice-Chairman. I will take two or three minutes more.

Sir. I do not know for how many years you have been here in Parliament. Here also the quality, as also in State Assemblies, of the people's representative has also been coming down to such an extent. Previously we used to come hereby *rickshaws* and then by taxis. Now taxis are very costly. Now I find, Mr. Vice-Chairman—it is a very interesting subject and I would request the Prime Minister to examine it - many Members of Parliament, people's representatives, have got posh cars to come to Parliament. Similar is the case with MLA's. Where does the money come from? Where is the nexus? We cannot afford it.

Mr. Vice-Chairman, I am all along talking of the system, and I want that system to be changed. For that purpose, a survey should be made of all the States about the people's representatives, how they behave where money comes from. Since we politicians have got a nexus with bureaucrats and industrialists, the entire system has been degenerated. Mr. Vice-Chairman, Sir, I am only against that system. These industrialists who have been helped one way or another are damaging the system by creating a parallel economy. I would request the Minister, through you, Mr. Vice-Chairman, that let us show to the people that this Government is not only passing laws like the Anti-Corruption Bill but they also desire to implement it. I do not want to quote the names of any industrialists. But take, for examples, the Hindujas who had taken over the job on behalf of Government as agent for the last many years... (*Interruptions*) Even the Janata Government Prime Minister, had to divert his plane to get down at Frankfurt on way to Tehran to arrange meeting of somebody with Hinduja. (*Interruptions*) What does it mean? The day before yesterday, Mr. Hegde who is a great friend of mine, who talks of value systems or moral values, etc., said something. But his Chief Secretary, when he said that he has not asked for the tapping ..(*Interruptions*)

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala): But he has resigned, upholding those moral values. (*Interruptions*) You are immersed in corruption but you are... (*Interruptions*)...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal are not lagging behind They are at par with all the baser values, on the contrary. (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: He denied last week. What happened to the moral values last week when he it? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): We are not discussing Mr. Hegde now. (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: We demanded a judicial inquiry. Why don't you order a judicial inquiry? (*Interruptions*) We want a judicial inquiry.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): These very friends ...(*Interruptions*)...those who are protesting now, have been issuing statements condemning Mr. Hegde for his actions. Today Mr. Subramanian Swamy has stated that he had conducted an inquiry on behalf of their party and he has stated that he has conclusive evidence to prove that the Chief Minister gave the orders. (*Interruptions*) This is very unfortunate. This is double standard. This is hypocrisy. This is a deliberate attempt to cover the truth. (*Interruption*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Kindly take your seats, Mr. Kulkarni, kindly finish now.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: We are discussing the Prevention of Corruption Bill.

SHRI A. G. KULKARNI: I am discussing the Prevention of Corruption Bill. But the Prevention of Corruption Bill is the outcome of the system, the rotten system. Those who are sitting in glass houses should not throw stones at others. This is an old and wise statement. I think those who have taken the vow at Mahatama Gandhi's Samadhi while assuming office have degenerated politics to such an extent that they have no right to talk of value systems. (*Interruptions*) The Prime Minister of this country has appealed to his partymen to crush these peddlars and power brokers. (*Interruptions*) You are a new Member.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: I on a point of order, Sir. According to Rules of Procedures and Conduct of Business in this House, is there any distinction between a new Member and an old Member? Can you make any distinction? I want a ruling on that. Last time also he called me a new Member. I was a Member of the Lok Sabha.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I never meant anything.

SHRI YASHWANT SINHA: I am on a point of order, Sir. This debate had proceeded in a very cool and reasonable manner. But it is very unfortunate that the rulig party is trying to inject politics into the discussion on a Bill which has such serious consequences.

SHRI A. G. KULKARNI: I am not injecting politics. I am bringing out the defects of the political system only. Please join me in it. The political system has debased itself. All that I said, Mr. Vice-Chairman, is that these political parties which took a vow before Mahatama Gandhi's Samadhi have degenerated within two years...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): You have already said that.

SHRI YASHWANT SINHA: No, Sir. This is politics. This cannot be allowed. (*Interruptions*) We have not talked about all that.

SHRI A. G. KULKARNI: I understand that, Sir. The political parties which went and took a vow that they would bring in a new generation of politics and a new system in politics have degenerated to such a level.

Sir, while concluding, I will request all my friends on this side and also on that side that we should improve the quality of politics. Let us improve the system in which the industrialists, the bureaucrats and the politicians have formed a nexus. It may be Thapar or Hinduja or Ambvani or Bombay Dyeing or anybody else ... (*Interruptions*) Can I disclose the connections? If the hon. member wanted to know the connection between Hinduja and his party, I can disclose it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Kindly conclude, Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI: I am concluding. Sir, I will request the hon. Minister who is a young Minister to please give strength to the Prime Minister to crush this type of peddlars and power brokers who have entered into the political system. For this purpose, I support the Bill.

डा. अबरार अहमद खान (राजस्थान): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हू कि उसने भ्रष्टाचार निरोधक प्रावधानों को एक ही एक्ट के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया है तथा भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में न्यायिक और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया है । भ्रष्टाचार की व्याख्या अति विराट और व्यापक है तथा इसको रोकने के लिये केवल एक हल नही हो सकता । इसको रोकने के लिये भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है । इस दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार को मैं तीन श्रेणी में बांटता हू ।

महोदय, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता की न्यूनतम पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न भ्रष्टाचार, जिसमें मकान, परिवार का सहज पालन, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल आते हैं । जब व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाता है, समय और काल के अनुसार जो आवश्यक वस्तुए हैं, उनकी पूर्ति नही होती है तो भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है । इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है तथा जो भी संभव हो, गलत तरीका अपनाता है । इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उपाय कोई सरकारी बिल अथवा उसको समाप्त करने वाला कानून सफल नहीं हो सकता है । इस प्रकार से उत्पन्न भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम करें, उनकी पूर्ति बढ़ायें तथा नीचे के स्तर पर मजदूरी बढ़ाकर कम से कम संख्या में वेतनमान निश्चित करें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की दूसरी सीढ़ी में उच्च मध्यम-वर्ग आता है, जो अपनी आवश्यकताओं से अधिक साधनों का संकलन करता है, पूंजी जोड़ता है, जायदाद बनाता है । अतः इन साधनों के संकलन, पूंजी के एकीकरण व जायदाद को प्रतिष्ठित करने के लिये उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति भ्रष्टाचार की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है । इस सीढ़ी पर खड़ा होकर भ्रष्ट व्यक्ति आम आदमी के प्रत्येक सामान्य कार्य में बाधक बनता है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कल सुबुल साहब कह रहे थे और अभी हमारे बंहल साहब ने कहा, मैं भी उसी बात को दोरा रहा हूं । महोदय, कोर्ट के सामने पैसे लेना, राशन-कार्ड बनाने मे रिश्वत लेना, नगरपालिका में मकान का नक्शा बिना लेन-देन के पास न करना, पटवारी और तहसीलदार द्वारा जमीन के मामलों को बिना पैसों के बात न करना, राज्य सचिवालयों में फाइल का बिना पैसों के पहिये लगाये आगे न बढ़ना, डाक्टर द्वारा मौत से संघर्ष करते मरीज को बिना रुपयों की झलक देखे उसके बदन पर आला न लगाना, अध्यापकों द्वारा बिना ट्यूशन बच्चों को पास न करना, इंजीनियरों द्वारा ठेकेदार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करना, सीमेंट में राख मिलाना, बिजली का कनेक्शन न देना, आदि-आदि बातें शामिल हैं और इस प्रकार से भ्रष्टाचार से एकत्रित पैसे सामाजिक बुराईयों की नींव मजबूत करते हैं । इन सामाजिक बुराईयों में दहेज जैसे दानव को जिंदा रखना, शादी व जन्म-दिनों पर आनप-शनाप पैसा खर्च करना, नैतिकता को ताक में रख ऐयाशी और रंगरलियां मनाना है । दूसरी श्रेणी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक कार्य का निपटारा समय पर हो तथा प्रत्येक कार्य निष्पादन की अवधि निर्धारित हो तथा इस वर्ग में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय व संपत्ति का सही आंकलन हो तथा अधिक संपत्ति पाये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो । मैं आशा करता हूं कि यह बिल सरकार को दूसरी श्रेणी के भ्रष्टाचार के नियंत्रण में मदद करेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अन्य तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम सबको मालूम है कि कुछ वर्षों पहले जो गांव थे, अब कस्बों में बदल गए हैं और जो कस्बे थे, वह शहर बन रहे हैं। काले-बाजारियों एवम् उच्च श्रेणी के भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों ने इन कस्बों और शहरों के चारों और जमीनें खरीदी हैं। उच्च मध्यम-वर्गीय भ्रष्टाचार करने वाले ऊंची कीमतों पर रिहायशी प्लाटों के लिए जमीनें खरीदते हैं और इन जमीनों की ऊंची कीमतों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा खरीदने वालों को भ्रष्ट तरीके अपनाने के लिए बाध्य करता है। जमीनों की बढ़ी हुई

5.00 P.M कीमतों ने भी भ्रष्टाचार को पनपाया है। सरकार से मेरा सुझाव है कि अचल संपत्ति के हस्तांतरण और खरीद पर कठोर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए जिससे उच्च मध्यम वर्ग महंगी जमीनों को खरीदने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने पर उतारू न हो।

देश के औद्योगीकरण के साथ एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो उच्च श्रेणी का भ्रष्टाचार करता है। यह भ्रष्टाचार की तीसरी पीढ़ी है। इसमें रिश्वत देनेवाले और लेनेवालों की मिलीभगत होती है। इस श्रेणी के भ्रष्टाचार में उच्च श्रेणी के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो हर समय पैसा कमाने की हवस के शिकार रहते हैं जो मानवता के मूल्यों और दृष्टिकोण से कोसों दूर हो जाते है। इस श्रेणी में उच्च श्रेणी के अधिकारी, बैंकिंग संस्थाओं के व्यवस्थापक, बड़ी वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधक, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ सम्मिलित रहते हैं जो अपने भ्रष्टाचार से राष्ट्र के आयाम बदल देते हैं तथा पैसा कमाने की हवस में अंधे होकर उस पैसे की राष्ट्रीय उपयोगिता को भूल जाते हैं। अत. इस श्रेणी का भ्रष्टाचार एक राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जो राष्ट्र को खोखला कर देता है। ऐसे ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने दिसंबर 1985 से पहल की थी। इसमें पैदा हुए विरोध से उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है तथा इस तीसरी सीढ़ी पर खड़े भ्रष्ट लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल में रखे गए प्रावधानों के द्वारा इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, while welcoming this Bill, I want to ask one question. The Santhanam Committee has made one vital recommendation that Government should involve people's participation if they want to fight against corruption, because corruption is spreading from top to bottom level. The Prime Minister had rightly said once that "corruption is not only tolerated but it is considered as a hallmark of leadership." If I have to become a leader, I should also be corrupt because that is the charactaeristic of leadership. If this is the situation, we cannot take corruption in the way it has been taken in the Bill, although I welcome it, because some of the provisions are good.

But can you fight the menace of corruption? When Kulkarniji was talking, he was rightly saying that the whole system has become so bad. Then the question is how to change the system? By enacting a law? I do not think that we can change a system. But law can be a lever in the hands of the people as people's participation is a very vital thing. Even in U.S.S.R. yesterday somebody mentioned that Russian progressives who want to take their society forward, there the bureaucracy has a nexus with the politicians, party bureaucrats, who were becoming a hurdle to progress, there also a parallel economy was developing and corruption was also a very important feature for them in the socialist society, where you cannot build an extra house of your own, you cannot have any show type of capital like factories and other things which you control. So, once a laxity is shown, then corruption spreads and the system becomes corrupt, because all who have evolved the system, all who are in the system, all who are managing the

[Shri Chimanbhai Mehta]

system, all are responsible in this matter. Kulkarniji gave the right example of Hindujas. We have discussed about Mr. Lalit Mohan Thapar here. He was caught under FERA violation. He apologised, and at mid-night, the Supreme Court allowed bail to get that man out of jail.

[**The Deputy Chairman** in the Chair]

And then after some time, the man got elected as the President of the Association of Chambers of Commerce and Industry, one of the highest body of the industrialists and traders of this country. He is the President and our dignitaries go and make inaugural speeches, Keynote speeches; Ministers also go and important people go and now when I am asking a question about L. M. Thapar, I am told the matter is *sub judice*. What is *sub judice*? It is because you do not want this to be revealed. Whether it is Thapars, whether it is Reliance, whether it is Bombay Dyeing, whether it is Hindjas, and now Lalit Suri and others there is a clear case of FERA violation and we talk of investigating those things.

This is the way we are tackling corruption.

The Prime Minister had rightly warned in 1985 that we are going absolutely in a wrong direction. I have also reproduced his quotations in one booklet. Some of them are very important. There is lack of conviction on our part. We know something is bad but cannot speak. "The best amongst us lack conviction." My elderly colleague wondered how people afford to buy cars when we are not able to afford auto-rikshaws. It is a fact. Some people can buy cars, luxurious cars. Where from do they get money? Our Prime Minister had also said—these are his words—"Our legislators magnify manifold conspicuous lack of social ethics."

This is where we have gone and how our legislators, our MPs our MLAs are behaving, and this was noted by the Prime Minister in December 1985, and since these three years, the situation has further deteriorated. How are we going to improve the situation? This is a very important thing, because everybody knows the source of corruption. There are politicians, bureaucrats, vested interests and others like smugglers, the mafia, and there is a nexus between them and this nexus is growing.

How staggering is the corruption? Partly, in my view ,taxation system is also responsibile. I have been saying since long that taxes that were in the year 1947-48, around Rs. 400 crores, have gone beyond Rs. 44,000 crores. Indirect taxes have gone up from Rs. 300 crores to beyond Rs. 30,000 crores. And this indirect taxation has become a very important point of evasion because most of the time some of the industrialists are wasting on how to evade taxes. They always think how they can make black money, how they can run a parallel economy. Therefore, it is the taxation system which requires to be rationalised. We are not discussing that point. Madam, perhaps, we are the topmost country in the world, having a record, in relation to evasion of taxes. This has been brought out by the report of the National Institute of Public Finance and Policy which was published in March, 1985. This document was discussed in our House also. It has been estimated that the extent of evasion is between 18 and 21 per cent in India of G.N.P. How does this compare with the extent of tax evasion in other countries? In the case of Australia, it is 11 per cent; Australia—8 per cent; Canada—4 per cent; Denmark— 12 per cent; France— 8 per cent; Japan— 4 per cent and even U.S.S.R. has been mentioned— 10 per cent; We occupy the top position in the world in the matter of tax evasion! This is what has been revealed by the statistics that have been given.

Madam, our attention should be directed to the question of the taxation system; how we can improve upon it; how we can rationalise it. We should also go in for reforms in the electoral system. We know the way we get money for the purpose of elections. Nobody is accountable. You may be able to control corruption partly

by this bill. But is a legislator accountable to his own colleagues? If I am a Minister, am I accountable to the legislators? Am I accountable to the party or not? (*Time-bell rings*) Is this my behaviour?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I am concluding. This is a very vital point. You cannot fight corruption unless you have inner party democracy in every party. I am not saying this in relation to any one particular party. (*Interruptions*) This applies to almost all political parties. We know, where they are ruling in the States, how the Ministers are behaving, how the Chief Ministers are behaving. I do not want to discuss this point here in the House, about what is happening in the States. But everybody knows how they make money, how they evade taxes. This is the system. This is inherent in the system. Therefore, let us not indulge in party politics here. There is no innerparty democracy in most of the political parties and therefore, the leader behaves like a boss. Therefore, corruption is regarded as the hallmak of leadership. That is why we are in such a position that we see today. Therefore, I would request the hon. Minister to consider all these points. Anyway, to the extent this Bill goes, I welcome it and wholeheartedly support it. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, I can call upon the hon. Minister because the time allotted for this Bill is over. But there are six or seven Members more to speak.

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): We can extend the sitting. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will also require some time.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will require only twenty minutes.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I have to speak on the Third Reading.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I think, there are only two Members to speak on the Third Reading, including Mr. Ram Awadhesh Singh. You can give three minutes each to our Members.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Dronamraju. He is not here. Dr. Ratnakar Pandey.

अच्छा आप लोग तीन तीन मिनट बोल लीजिए और संक्षेप में अपनी बात कहिए।

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, किसी ने विनोबा भावे से पूछा कि आप सदाचार पर बहुत भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते हैं, तो विनोबा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को आज शिष्टाचार की संज्ञा दे दी गई है समाज में और चारों ओर भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनकर छाया हुआ है। ऐसे में भ्रष्टाचार के बारे में न कहना ही उचित है।

यह जो भ्रष्टाचार निवारण विधेयक लाया गया है उसका स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। केन्द्रीय सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कानून को और कड़ा करने के लिए भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई को जल्दी निपटाने के लिए यह कानून सदन में रखा है। लोक सभा इस पर पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुकी है आज राज्य सभा के समक्ष है। भ्रष्टाचार को रोकना बड़ा कठिन काम है क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकतर लोगों के जीवन का अंग बन गया है। इस बात को महसूस किया सरकार ने कि भ्रष्टाचार सामाजिक बुराई से फैल रहा है और उस पर नियन्त्रण किया जाये। जो अब तक की व्यवस्था थी चाहे संथानम कमेटी की रिपोर्ट हो चाहे किसी वैदलिंगम या और किसी कमेटी की रिपोर्ट हो उसे पूरा परिवेश तो नहीं दिया जा सका। अब इस विधेयक से सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले को निपटाने के लिए 20 अदालतें बनाने की बात की है। अदालतों में विलम्ब होने के कारण भ्रष्ट अधिकारी जो मनमानी करते थे वह इससे समाप्त हो रही

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

है। नये जजों को नियुक्ति में जो विलम्ब होता है उसे भी 20 अदालतों के माध्यम से हल किया जायेगा। सरकार चाहती है कि मशीनरी इतनी मजबूत हो कि मुकदमें जल्दी से जल्दी न्यायालय में निपट जाये और भ्रष्ट अधिकारियों को विलम्ब का लाभ न मिले। इस विधेयक में बहुत सी अच्छी बातें हैं।

पहले तो हम लोगों को बोलने ही नहीं दिया जा रहा था और अब आपने समय निर्धारित कर दिया है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन आपके निर्देश और आदेश को संरक्षक के रूप में मानते हुए थोड़े भाव हम व्यक्त करेंगे।

आज चारों ओर भ्रष्टाचार की बात होती है। जब राजीव गांधी ने सत्ता के दलालों को बेनकाब करने की बात की तब सारे जो सत्ता के दलाल हैं वे परेशान हो उठे। मैं समझता हूं जो शासक दल की नीति है उसी की तहत इस भ्रष्टाचार निवारण विधेयक को लाया गया है। अभी इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी और उनके हत्यारों को फांसी दी गयी। जब ऐसे-ऐसे दल हमारे देश में हों जो इन्दिरा गांधी के हत्यारों की वकालत करने वालों को इस सर्वोच्च राज्य सभा के सदन में भेजें तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है...

SHRI YASHWANT SINHA: This is most objectionable. This cannot be allowed to go on record.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : आपने कहा सदन में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? **(व्यवधान)**

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैंने कहा इस सदन में चुन कर भेजा जा रहा है। इन्दिरा गांधी जिनको दुर्गा का अवतार कहा जाता है उसकी हत्या करने वाले की वकालत करे... **(व्यवधान)**

इन्दिरा गांधी जैसी सर्व सम्मान विश्व नेता के हत्यारों की वकालत करने वाले इस सदन में आये तो इससे बढ़ कर मैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं मानता। मैं इसको डंके की चोट पर कहने को तैयार हूं। मैं इसको सार्वजनिक जगहों पर और इस सदन में प्रस्तुत करूंगा। **(व्यवधान)**

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, we protest. This is most objectionable.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: It is quite obvious whom he is referring to.

उपसभापति : किसी का नाम नहीं लिया।

श्री यशवंत सिन्हा : दल का क्या मतलब होता है?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं... **(व्यवधान)**

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It this? Maintain some standard.....

He has saved an innocent person.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It is the Supreme Court which has acquitted him. *(Interruptions)* We have faith in the courts.

श्री उपसभापति : आर्डर प्लीज।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने इसी सदन में मांग की थी कि कांग्रेस से निकाला गया एक व्यक्ति सी० आई० ए० का एजेंट है। मैंने आरोप लगाया था कि हजारों एकड़ जमीन पर उसने ट्रस्टों के तहत कब्जा किया है और भूतपूर्व राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दो दिन पहले भारत सरकार को आदेश दिया था कि उसकी जांच कराई जाये। पिछली बार गृह मंत्रालय की बजट मांगों पर बोलते हुए मुझे आश्वासन दिया गया था कि उसकी जांच रिपोर्ट रखी जाएगी। वह व्यक्ति

आज एक फकीर बना हुआ है । जो कांग्रेस दल से निकाल दिया गया, जिसने न जाने कितनी निर्मम हत्याएं कराई अपने कार्यकाल में, मुख्य मंत्री रहते हुए... (व्यवधान) महोदया, मैं भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पर बोल रहा हूं । आत्माभिव्यक्ति की इस देश में शिष्टापूर्ण ढंग से आजादी है, उस पर आप लोग बंधन न लगाइये । मैं कह रहा था कि उस व्यक्ति ने सत्ता में रहा हुए न जाने कितने भ्रष्टाचार किये और विदेशी ताकतों से मिलकर इस देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की । उस व्यक्ति ने अपने लड़के को वित्त मंत्री रहते विदेशी बैंक में लाखों रुपये महीने की नौकरी दिलवाई और न जाने उस बैंक की इस देश में कितनी शाखायें खुलवाई । उसने अपने मख्य मंत्रित्व काल में न जाने कितनी झाड़ियों के नाम पर, पौधारोपण के नाम पर 90 लाख रुपये ले लिये । वैसा व्यक्ति, यह हमारी सरकार की कमजोरी है कि आज खुले आम चेलेंज दे रहा है, चारों तरफ चेलेज दे रहा है । हमारी सरकार अगर हम संसद् सदस्यों की मांग पर कड़ाई से कदम उठाती तो आज यह नौबत नहीं आती । मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें, चाहें इधर के बैठे हुए लोग हों या उधर के बैठे हुए लोग हों... (व्यवधान)। मैं घोषित कर चुका हूं । सारे लोग अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें । आज जनता के बीच में इस बात की आवश्यकता है कि सारे राजनैतिक दलों के जन प्रतिनिधि डंके की चोट पर, चाहे शासक दल के हों या विरोधी दल के हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, विरोधी दलों में भी ऐसे लोग है जो लाखों करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक बने हुए हैं । ऐसे लोगों को भी जनता अच्छी निगाह से नहीं देखती है । इसके साथ-साथ एक और भी व्यक्ति पर आरोप लगता है और मुकदमा चलता है और उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि उसके दामाद ने एक टेलीफोन उपकरण परियोजना स्थापित करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अपने परिवार के स्वामित्व वाले स्टूडियो की जमीन के उपयोग में परिवर्तन और उसके मूल्यों में कमी की । भूमि के संबंध में छूट... (व्यवधान) मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम सब जानते हैं । कृषि विपरण समिति की जमीन खरीदी और रावल स्टील लिमिटेड की स्थापना की, यह कोर्ट ने सिद्ध किया है । आज इस देश में सारी मानवता की रक्षा करने वाले, दबे हुए पिछड़े हुए लोगों के नेता श्री राजीव गांधी, जो सारी दुनिया के नेता हैं, अपने भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे-ऐसे लोग ही लगाते हैं । जो लोग हाजी मस्तान जैसे तस्कर के पैसे पर इस देश में जनतंत्र लाना चाहते हैं, चुनाव लड़ते है...इस सदन के माध्यम से ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिये । माननीय उपसभापति महोदया, जिन लोगों की कोई नीति नहीं है, जो हिन्दू-मुस्लिम का खून बहाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के नाम पर सारे देश को बरबाद करना चाहते हैं ऐसे लोगों की सहायता लेकर कभी विरोधी एकता का किसी को नेता बनाया जाता है और फिर दूसरे दिन दूसरा आदमी आकर सन्यासी के रूप में उनका नेता बन जाता है । ऐसे लोग जनतंत्र की रक्षा करेंगे, भ्रष्टाचार मिटायेंगे ? ऐसे लोग हमारे देश की महिमा, गरिमा और महत्ता जो है उसको नष्ट करेंगे । उपसभापति महोदया, मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक व्याप्त है । मैं बधाई देना चाहता हूं कि उस मुख्य मंत्री को जिसने कल इस्तीफा दिया टैपिंग आरोप लगने पर । मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसा मुख्य मंत्री जिसने इस्तीफा दिया है, वह टेलीफोन टेप कराता है, अपने दल के लोगों के टेलीफोन टेप कराता है, दूसरे दल के लोगों के

[डा० रत्न कर पाण्डेय]

टैलीफोन टैप कराता है, प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन टैप कराता है, ऐसे लोगों.....

SHRI YASHWANT SINHA: It is not relevant. It should not go on record.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अगर कानून में कड़े दंड का प्रावधान न हो तो आपको इस कानून में परिवर्तन लाना चाहिये। अब यह देश इन चीजों को बर्दाशत नहीं करेगा।...(**व्यवधान**)... इन शब्दों के साथ मैडम "हवा के दोश (कंधे) पर लहराता परचम (झण्डा) हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा तमाशा हम भी देखेंगे।"

भ्रष्टाचार के विरोध में हम जो कदम बढ़ा रहे हैं, करप्शन को समाप्त करने के लिये उनका कड़ाई के साथ पालन करना चाहिये। हमारे मित्र जो जनतंत्र में विश्वास नहीं करते है केवल सत्ता प्राप्ति में विश्वास करते हैं, ऐसे तत्वों के ऊपर भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो बन रहा है उसमें रोक लगाने के लिये प्रावधान किये जाने चाहिये।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक का समर्थन करता हूं! ...(**व्यवधान**)...

श्री राम अवधेश सिंह : दिल्ली में भी टेलीफोन टैप होते हैं इसलिये प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिये...(**व्यवधान**).. एम० पी० लोगों के टेलीफोन टैप होते हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: We have heard a long debate on this Bill which was brought before the Parliament last year. A number of Members have spoken on this Bill. I am grateful to them for the broad support extended to this Bill.

This Bill is a consolidating and amending Bill. I wish to draw the attention of this House to the fact that we are consolidating in one Bill provisions which are now scattered in many enactments. We have taken provisions from the Prevention of Corruption Act, 1947, the Criminal Law (Amendment) Act, the Criminal Law (Amendment) Ordinance of 1944, the Indian Penal Code and we have brought them in one Bill so that the prosecuting agencies as well as the courts can deal with corruption cases in a comprehensive manner applying one consolidated Act. We have also taken this opportunity to amend the laws based upon our experience over the last 40 years. References were made to the Santhanam Committee. It is true that the Santhanam Committee did pioneering work but we found that in the enforcement of these laws there were several difficulties, several impediments and, therefore, we had to constitute other Committees to look into these matters.

Madam, in the first place we had a Committee headed by the Additional Director of the CBI and in which officers belonging to the Anti-Corruption Bureau of the States were represented. That Committee gave a report. Then we had a Committee under the Cabinet Secretary and that Committee also gave a report. It also gave the draft of a comprehensive Bill. The Bill which has been passed by the Lok Sabha and which is now before this honourable House is based upon the draft comprehensive Bill which was prepared based on the report of these two Committees.

Madam, I wish to invite attention of the hon. Members to some of the more important features of this Bill. Firstly, we have taken the opportunity to explain and define more precisely the expression 'public servant'. I am grateful to the hon. Members for welcoming the new definition which embraces cooperative societies, educational institutions and other public institutions.

One of the hon. Members raised question about the position of the Ministers. I think the position is beyond doubt. Ministers are public servants. They have always been public servants

and they are public servants under this law and Ministers will come under the purview of this Bill.

AN HON. MEMBER: What about MPs?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. A question was asked about the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly. Madam, under the law declared by the Supreme Court, a Member of Parliament or a Member of the Legislative Assembly *per se* is not a public servant. But there can be a number of situations where an MP or an MLA holds another office and discharges other duties which will bring him under this Bill. If he holds another office in a cooperative society, if he holds another office in a public institution or if he discharges certain duties which will come under the definition of public duty clearly, then, he would be within the definition of 'public servant' under this Bill. But these are matters in which you cannot make on a prior assumption. One has to look into the facts of each case and then the courts will decide on the facts of that case.

Madam, the next important innovation made in this Bill is that we have taken power, concurrent power, for the Central Government to appoint courts of special judges. Corruption cases can be tried only by a special judge. The power of the State Governments to appoint special judges is intact. But we have taken concurrent power because our experience shows that State Governments are reluctant to constitute courts of special judges or earmark judges to specially deal with corruption cases. We have considerable difficulty in prosecuting cases launched by the CBI. A large number of cases are pending. CBI has 482 cases pending for trial for over 5 years. 549 cases are pending for trial between 2-5 years, 284 cases are pending for trial between 1-2 years and 311 cases are pending for trial for periods less than a year. We have written to the State Governments that they should constitute more courts of special judges, or they should earmarked more courts and designate them as courts of special judges. We think that by taking this power, we can also constitute courts of special judges and I would take this opportunity to appeal to the State Governments to kindly respond more favourably and constitute courts of special judges which can try offences under the Prevention of Corruption Act.

Madam, delay, I believe, is the single biggest reason which defeats our fight against corruption, particularly, delay in courts. If we must control corruption I certainly do not hope that in my lifetime we will be able to eradicate corruption but we must control and curb corruption—we must ensure that there is swift and deterrent punishment to the corrupt. I think there is no purpose served by punishing somebody 20 years later because invariably you will not get a conviction after 20 years. Therefore, we have provided in clause-4 sub-clause 4, that a special judge shall hold the trial on a day-to-day basis. We have also provided in clause 19, sub-clause 3, that technical defences and technical pleas should be taken at the earliest opportunity and if they are not so taken, they cannot be taken at a later stage or before the higher court. We have provided that the High Court and other courts shall not stay the trial except in two situations. I can only appeal to our courts, particularly to our High Courts, that they should not interfere with the trial of corruption cases on petitions which are filed before them and which in my experience contain mostly frivolous and flimsy grounds. The accused is always anxious to delay the trial. He knows as much as we know that delay helps the accused and delay thwarts the purpose of the prosecution. I would again take this opportunity to appeal to the courts not to exercise their power under article 226 or article 227 or under section 438 of the Criminal Procedure Code, except in rare cases. Two such situations are provided for in clause 19, sub-clause 3 and I hope, there will be no other situation which will require High Courts to interfere with the trial of the corruption cases.

[Shri P. Chidambaram]

Madam, another major innovation that we have introduced in this Bill is that we have provided for a minimum punishment of imprisonment, whenever anybody is found guilty under this Act. Under the earlier law, he could get away with a fine. He could get away with a sentence of imprisonment until the rising of the court. I cannot think of anything more farcical than a sentence of imprisonment which says that he is sentenced until the rising of the court. I know of cases where the sentence has been passed at 4.55 and the court rises at 5 O' clock. Therefore, we are providing that there shall be a sentencce of minimum imprisonment and I am sure, with this deterrent punjshment, it will, to a large extent, control the tendency to corruption. Madam, I wish to draw attention to clause 29 of the Bill which refers to the Criminal Law Amendment Ordinance. The Criminal Law Amendment Ordiance is a powerful weapon, which unfortunately, had gathered dust over the last 40 years. We have taken it out of the shelf, we have dusted it and we are employing it in many cases. The Criminal Law Amendment Ordinance has been invoked in a number of important cases recently. A comment was made that our drive against corruption is against petty officials. Since I took over, under the guidance of the Prime Minister, I have laid down that while we will try to register cases against people at lower levels because that is the cutting edge of the administration the thrust of the drive of the CBI will be against people occupying high positions and high offices. I believe that if you control corruption at the highest levels of the administration, each level of administration will ensure that corruption is controlled at the level below. And this philosophy and this system of control will percolate to the levels below.

Madam, I wish to give some figures about the special drives launched by the CBI in the last 2-1|2 years. Under the system of special drives, in the period from October 1985 to December 1985, the CBI registered 53 cases and disposed of 51 cases; 35 of them were referred for major penalty proceedings and 9 for trial in criminal courts. In the year 1986, under the special drive system, the CBI registered 175 cases and has already disposed of 165 cases; 81 of such cases have resulted in major penalty proceedings and 42 cases in trial before the criminal courts. In 1987, the CBI registered 143 cases and we have already disposed of 73 cases; 50 have resulted in major penalty proceedings and 12 in trial in criminal courts. Madam, we find that the areas which are prone to corruption are nationalised banks, Income-tax department, the Railways, Food Corporation of India, Customs and Central Excise, Chief Controller of Imports and Exports, Posts and Telegraphs and Central Public Works Department. Public sector undertakings are also, to some extent corruption prone. We have identified corruption-prone areas and we continue to intensify the drive in corruption-prone areas. Again, Madam, some other statistics would be of some interest to hon. Members. In the special drive cases, the thrust is against gazetted officers in Group A services and gazetted officers in Group B services. The bulk of the cases are registered against gazetted officers belonging to Group A and Group B. Madam, in the course of these searches, we have unearthed vast amounts of immovable property and movable property. For example, in 1985, the amounts unearthed are cash, bank balances and shares of a value of Rs. 56.46 lakhs. In 1986, this went up to Rs. 1,05,00,000|- In 1987, it was Rs. 90.96 lakhs and in 1988 up to June it is Rs. 97.53 lakhs. If you look at the movable assets like TV, VCR, car, Fridge, jewellery; etc.; in 1985, we unearthed assets of the value of Rs. 88.99 lakhs; in 1986, Rs. 98.51 lakhs; in 1987, Rs. 2,09,00,000|- and in 1988, in the first six months, Rs. 73.41 lakhs. If you look at the immovable assets, in 1985, we unearthed assets worth Rs. 80.35 lakhs; in 1986, Rs. 1,58,00,000|-; in 1987, Rs. 3,29,00,000|- and in 1988, in the first six months, Rs. 1,09,00,000|-. It is, therefore, not correct to say that the drive against corruption has slackened. On the contrary, I dare say that, ever since the Prevention of Corruption Act

was made, there has been no comparable 2-1|2 years when we have launched such a sustained and intense drive against corruption as we have done in the last 2-1|2 years.

Madam, I made a reference to the Criminal Law (Amendment) Ordinance. Under this Ordinance pending trial we can attach ill gotten wealth and propert. This Ordinance was so rarely invoked in the last forty years that most officers did not even know about the existence of this Ordinance. In the last two and a half years we have invoked this Ordinance against a former Director General of Police (Assam) and we have attached movable property of the value of Rs. 24 64 lakhs and immovable property of Rs. 6 lakhs. We have attached property of an Assistant Passport Officer of the value of Rs. 13.80 lakhs. We have attached property belonging to a manager of a nationalised bank and we have attached property of a Joint Secretary in the Ministry of Law. In four more cases attachment proceedings are in process under the Criminal Law (Amendment) Ordinance. All these figures which I have given will clearly establish that the drive against corruption is sustained, intense and relentless We have also revived the system of publicising this in newspapers. If you had seen yesterday's newspapers you would have seen the press statement relating to the month of June. One hundred and nineteen cases have been publicised in the newspapers. I do not know whether we should go further Perhaps we should go further. In cases where we secure convictions or secure dismissal orders in departmental proceedings we now give a broad indication of the kinds of officers who have been punished. Perhaps we should go further and publish their names and addresses in the newspapers. Publicity is a deterrent to corruption.

I don't think I need refer to any particular clauses of the Bill The clauses are quite clear. The explanatory note on clauses amplifies each clause. I don't think there has been any serious dispute about any particular clause. I know my friend, Mr. Pawan Bansal, referred to one or two clauses. But I think they ae easily explained. Explanation (a) to Clause 7 deals with a case where it would not be an offence under Clause 7 but would be an offence of cheating. I have read the explanation again. I believe it is correctly drafted. As far as Clause 7, sub-clause (e), concerned, I agree, with him that the word 'erroneously' is redundant. But if he will read it again carefully the addition of the word 'erroneously' does not add to or subtract from the thrust of that clause. I, therefore, would leave it there. I do not think there is any other clause on which any serious doubt was raised. I sincerely hope that I have answered the general points made by honourable Members. I entirely agree with several honourable Members who said that it is not difficult to locate a corrupt officer. Corruption is like a stink. You cannot contain it very long. If an officer is corrupt, if his reputation is doubtful, it will not take very long for the organisation or the people in that area to know that he is corrupt. But unfortunately, over the years we have had a system supportive of corruption. We have become very supportive of corruption. If we want to get a driving licence or a ration card, we do not thing twice before shelling out a few rupees, by whatever name you call it, speed money or a tip. All this really amounts to corruption. We have become very tolerant of corruption. We have also become tolerant of corrupt officers. I get a large number of representations from people saying, "Please wind up the case".... (*Interruptions*) I am not generalising. We have become very tolerant of corrupt officers....

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Are you referring to Andhra Pradesh Govenment?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Whatever we do we cannot tackle every case of corruption There are severe limitations of finance, severe limitations of manpower severe limitations of time The CBI, for example, can register only about 1200

[Shri P. Chidambaram]

cases a year. A comment was made: "Why don't you register 10,000 cases?" I would like to register 10,000 cases but I would need a budget five times the size of the present budget. I would need manpower, five times the size of the present manpower. So, whatever resources we have, whatever time we have, whatever manpower we have, must be used to fight corruption in the most crucial areas and that is the philosphy which this Government is following. We are fighting corruption in the most crucial areas, we are fighting corruption in the most critical areas, and we are fighting corruption in the most corruption-prone areas.

Madam, I ask for the unanimous support of this House for this Bill which, I am sure, when it becomes a law, will become a powerful instrument to fight corruption, not only in the hands of the Central Government, but also in the hands of the State Governments.

Madam, I would like to make one last point. The CBI derives its jurisdiction from the Delhi Special Police Establishment Act which is jurisdiction obtained by the consent of the State Governments. The Prevention of Corruption Act is not an instrument only in the hands of the Central Government, but it is an instrument in the hands of the State Governments also Therefore, it is the State Governments which must use this instrument and fight corruption. The CBI will only step in in the most deserving cases in the most important cases, and the smaller cases, petty cases, must be fought by the State Governments. For example, I heard a complaint that when the nationalised banks lodge a complaint with the State police, the State police people are reluctant to take up such cases. How is it possible for the CBI to take up all the cases of corruption which are in the nationalised banks? So, it is the State Governments the State police and the State prosecuting agencies, which must step in and bear the burden of the fight against corruption. Unfortunately, what we find is that the State Governments are unwilling to fight corruption and they turn round and say that the Central Government must fight corruption. But the Central Government has severe limitations and we can only do so much. In fact, we are doing more than what our resources permit. The State Governments must put up an intensified fight against corruption.

Madam, once again I thank the honourable Members and seek their unanimous support to this Bill. Thank you, Madam.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस विधेयक में लिखा है, "इसका प्रभाव जम्मू काश्मीर राज्य के सिवाय सपूर्ण भारत पर होगा और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू होगा। "मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि भारत के नागरिक जो भारत के बाहर कहीं भी बसते हैं, उन पर तो यह लागू होगा, लेकिन जम्मू काश्मीर राज्य पर लागू क्यों नहीं होगा? दूसरी चीज एक बार जम्मू काश्मीर में अभी इनकम टैक्स के छापे मारे गए। वहां उनका बड़ा भारी विरोध हुआ। तो जब भारत के निवासी दुनिया में कहीं भी हों उन पर यह लागू होगा, लेकिन जम्मू काश्मीर जो भारत का अंग है, वहां यह लागू क्यों नहीं होगा?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदया, मैंने गृह मंत्रीजी से एक जिज्ञासा की थी। एक ससद सदस्य के रूप में हम ने भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ज्ञापन दिया था। राष्ट्रपति जी ने उन आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार को लिखा था। यह मामला मैंने गृह मंत्रालय की मांग में भी उठाया था। महोदया, भ्रष्टाचार से सम्बन्धित वह मामला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार से सम्बन्धित

वह मामला है और गृह मंत्रालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है और उस में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उपसभापति : आखिर में जवाब देंगे। I shall now put the amendment of Mr. Sukomal Sen for reference of the Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—

1. Shri Dipen Ghosh
2. Shri K. Mohanan
3. Shri Parvathaneni Upendra
4. Shri N. E. Balaram
5. Shri Chitta Basu
6. Shri M. S. Gurupadaswamy
7. Shri Virendra Verma
8. Shri Murasoli Maran
9. Shri Atal Bihari Vajpayee
10. Shri Nagen Saikia
11. Shri Gurudas Das Gupta
12. Shri Aladi Aruna *alias* V. Arunachalam
13. Shri Darbara Singh
14. Shri Deba Prasad Ray
15. Shri Sukomal Sen

With instructions to report by the first day of the next Session."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: As the House has already rejected the amendment moved by Shri Sukomal Sen, I am not putting the amendment of Shri S. P. Malaviya to vote which is similar in nature. I shall now put the motion moved by the Minister to vote.

The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matters connected therewith as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 28 were added to the Bill.

Clause 29 (Amendment of Ordinance 38 of 1944)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I move:

"That at page 13, line 17 *for* the figure '1987' the figure '1988' be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 29, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

Clauses 30 and 31 were added to the Bill.

Clause 1 (Short title and extent).

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I move:

"That at page 1, line 5 *for* the figure '1987' the figure '1988' be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

[The Deputy Chairman]

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I beg to move.

"That at page 1, line 1, *for* the word 'Thirty-eighth' the word "Thirty-ninth' be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are some speakers at the third reading. Generally, 2 or 3 minutes are given.

Shri S. P. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इसमें एक तो जो यह बिल लोक सभा द्वारा 7 मई, 1987 को पारित किया गया था और आज 18 महीने बाद नौबत आई है राज्य सभा में इस बारे में यह बिल पारित किया जाए तो मेरा यह कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है . . . (व्यवधान) . . और कोई विधेयक लोक सभा में 18 महीने पहले अधिनियम किया जाए और राज्य सभा में 18 महीने बाद पारित होने की नौबत आए तो इसके माने हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और चिदम्बरम् जी ने माना है कि करप्शन को हम कम कर सकते हैं, इरेडिकेट नही कर सकते हैं । तो मेरे इसमें दो सवाल हैं । एक तो यह की आज जो हालत है आज जो मजिस्ट्रेट, दिल्ली के मजिस्ट्रेट है, विन चड्ढा का मामला इस संबंध में और फेरा जो वायलेशन में था, इस तरीके से मुकदमा लड़ा गया था कि मजिस्ट्रेट को अदालत से ही विन चड्ढा को रिहा कर देना पड़ा । तो जो कानून की कमियां है उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दूसरे, पवन बंसल जी ने भी अपने विचार-विमर्श में अपने सुझाव दिए थे कि कुछ संशोधन करना चाहिए । मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सैक्शन 19 की ओर, जिसमें Sanction for prosecution and other miscellaneous provisions...

और इस ओर मैं इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हू कि जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ यदि भ्रष्टाचार का मुकदमा किसी अदालत में दाखिल करना पड़ेगा तो उसके लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता का प्रावधान है इसमें और यदि वह राज्य सरकार का सरकारी कर्मचारी है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक राज्य सरकार उसकी अनुमति न दे । यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए मैं निवेदन करूगा कि यह जो धारा 19 है इसको खतम किया जाए क्योंकि अगर यह रह जाएगी तो इस कानून की जो मंशा है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अत में प्रैस काउंसिल की एक रिपोर्ट जो 5 अगस्त को इसी सदन के पटल पर रखी गई थी

9tn Annual Report of the Press Council of India

क्योंकि प्रैस वालों को भी इसमें संरक्षण मिलना चाहिए । जब भ्रष्टाचार का वह पर्दाफाश करे तो हमारी प्रेस कांउसिल

के पास ऐसी शिकायतें आई है कि जहां पत्रकारों की पिटाई की गई, उनको मारा गया, उनके कैमरे छीन लिए गए। प्रेस कांउसिल ने उसका विवरण अपनी रिपोर्ट में दिया है जो राज्य सभा में पेश की गई। उसमें कहा है चेयरमैन ने--

Ninth Report of the Press Council—laid in Rajya Sabha on 5th August.

The Report of the Press Council goes to indicate that there are very many cases in which the journalists have been assaulted for exposing irregularities in public life.

तो मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो लोग पब्लिक लाइफ में करप्शन को ऐक्सपोज करते है उनके जीवन को खतरे से बचाने के लिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभापति महोदया, इस बिल का सर्वोपरि स्वागत होना चाहिए और हुआ है क्योंकि जिस रोग के खिलाफ यह बिल लाया गया है वह राष्ट्रीय जीवन को बुरी तरह से ग्रसित किए हुए है। इसलिए इस रोग को खत्म करने में इस सदन के दोनो तरफ के सदस्यों ने समर्थन किया इसमें कोई शक नहीं है। जो शंका है वह यह है कि विधेयक पास हो जाने के बाद भी क्या सरकार भ्रष्टाचार के सही मुकाम पर हाथ डाल सकेगी ? यही शंका इसमें है। हम चाहते हैं कि इस शंका का निर्मूलन किया जाए। भ्रष्टाचार के मूल मुकाम हैं निजी संपत्ति। चोरी वहीं होती है जहां चोरी करने के बाद बचने की गुंजाइश हो। भ्रष्टाचार वहां होता है जहां बचने की गुंजाइश हो। जहां चोरी या भ्रष्टाचार करने के बाद बचने की गुंजाइश नहीं होती है वहां भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। जैसे चीन में या रूस में या बलगेरिया में या रूमानिया में निजी संपत्ति नहीं है। तो निजी संपत्ति अपराध करने के लिए, आर्थिक अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। यह निजी संपत्ति किसी सीमा तक हम रख सकते हैं। इसलिए अपराध करते हैं और बचते है।

दूसरा कारण हम लोगों के चलते है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जाति के जो लोग राजनीति करते है इसके चलते भ्रष्टाचार बहुत है। हम चुनाव में खर्चा करते हैं 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख तो वह कहां से लाएंगे। वह हम व्यापारियों से लेते है, अफसरों से लेते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते है तो वे हमारी नाक के सामने ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और चोरबाज़ारी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमको कोल इंडिया लिमिटेड के एक अधिकारी ने कहा कि उसको जब एक मंत्री ने कहा कि 50 लाख रुपया चंदा दो तो हम भी चाहेंगे कि उसमें से 15 लाख रुपया हम भी बचा लें। हम सच्चाई से इस बात को कह रहे हैं, आप सच्चाई से आंख मूंदना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ? आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बिल लाते है, दोनो बातें नहीं हो सकती हैं। आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए विधेयक लाते हैं और उसको सही मकाम पर हाथ डालने के लिए नहीं कहते हो।

तीसरी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों या प्राधिकारियों के जरिए चन्दा वसूलने की परिपाटी खत्म कीजिए। इनकमटैक्स के अफसरों से, सेल्स टैक्स के अफसरों से, कोल इंडिया लिमिटेड और पब्लिक सैक्टर के अफसरों से इस काम में आप मदद लेते है, उनसे हम लोग सहयोग करते है, जिसके हाथ में जहां सत्ता होती है उससे चंदा मांगते हैं। राज्य सरकार जिसके हाथ में है वह राज्य सरकार के अफसरों का इस्तेमाल करता है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचरियों का केन्द्र वाले इस्तेमाल करते है तो हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

महोदया, मैं एक कारण और बताना चाहता जो हूं कि सबसे बड़ा कारण है।

इनकम टैक्स की व्यवस्था जो हमारे देश में है उसमें ऐसा स्लैब बना हुआ है कि भगवान भी धरती पर उतर आये और कारखाने चलाये, उद्योग चलाये और

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

उससे जो आमदनी हो तो वह भी अपना रिटार्ड और हिसाब-किताब सही नहीं दे पायेगा। कौन होगा जो एक करोड़ रुपया मुनाफा कमायेगा और उसमें से 80-90 लाख रुपया इन्कमटैक्स में देगा। इस तरह ब्लैकमनी जनरेट होती है और ब्लैक मनी जनरेट होती है तो दूसरे भ्रष्टाचार की चेन शुरू होती है। ब्लैक मनी हमारे पास है तो हम पालिटिक्स को खरीदेंगे और पालिटिक्स के जरिये दूसरे ठेके, परमिट, कोटे लेंगे। इससे ब्लैक मनी जनरेट होगी। इस तरह से भ्रष्टाचार की एक चेन शुरू हो जाती है। इनकम टैक्स जिससे भारत सरकार को केवल दो फीसदी आमदनी होती है उस दो फीसदी आमदनी के चलते देश में करीब 30 हजार करोड़ रुपया ब्लैकमनी की पैनलल इकोनोमी कायम हो गयी। 30 हजार से 40 हजार...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : साठे साहब ने अपनी एक किताब में लिखा है ऐसा।

श्री राम अवधेश सिंह : कुछ ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे सही मुकाम पर पहुंचा जा सके। मैं अभी बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को जो मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है लेकिन मैं कांग्रेसी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि भ्रष्ट के मामले में उसने बहुत ठोस कदम उठाया है।

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : बिहार सरकार ने?

श्री राम अवधेश सिंह : हां, बिहार सरकार ने। उसने यह साबित किया है **(व्यवधान)** उस काम से राजीव सरकार की इज्जत बिहार में बढ़ी है। गांव-गांव में बढ़ी है इसमें कोई शक नहीं है। वहां भ्रष्टाचार था कि पूरी बिहार की अर्थ-व्यवस्था खराब हो रही थी। हजो मस्तान नरेन्द्र...

उपसभापति : नाम न लीजिए किसी का।

श्री राम अवधेश सिंह : उसको सस्पेंड कर दिया। इस काम के लिए बिहार के मुख्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद ने जो किया उसके लिए उनको अनेकों-अनेक बधाई। वह एक ध्रुवतारे की तरह से काम करने वाले है। **(व्यवधान)** आने वाले मुख्य मंत्री इसके विपरीत प्रदर्शन करेंगे। जब उनको वह जेल भेज देंगे तब राजीव सरकार की प्रशंसा घर-घर बिहार में होगी। उन के चेहरे पर जो भ्रष्टाचार का दाग है वह काफी हद तक मिट जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य : बहुत अच्छा बोले।

उपसभापति : ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए नहीं तो गाड़ी कहीं और निकल जायेगी।

श्री अश्विनी कुमार : यह जो बिल मंत्री महोदय लाये है इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं परन्तु एक छोटा सा लकूना है जिसका उदाहरण मैं उपस्थित करूंगा। धारा 19 की चर्चा मालवीय जी ने की जो अनुमति लेने की धारा है। अनुमति लेने का ज प्रश्न है इतना विकट है कई बार सरकार अपने कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाने की अनुमति देती ही नहीं और अगर देती है तो महीने, दो महीने 6 महीने कोई टाइम बाउंड नहीं है कितने दिन में अनुमति देनी है। इसी के कारण भ्रष्ट चार पनप रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, इंक्वायरी चली और वह इंडिक्ट हो गया है पर कोई एक्शन नहीं होता। एक उदाहरण स्पष्ट है। टाटा नगर के रेलवे के कुछ पदाधिकारी और टिस्को के कुछ अधिकारियों के ऊपर बिहार गवर्नमेंट के आई० जी० विजिलेंस ने रिपोर्ट लिखी। ये 13 लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है। इसके अलावा 8 या 9 रेलवे के थे और जब रेलवे बोर्ड के पास मामला आया तो उसके चेयरमैन ने उनके बारे में कोई अनुमति नहीं दी और कोई कारण भी नहीं दिया। आखिर, आई. जी. विजिलेंस ने लिखा हुआ था कि वे भ्रष्ट हैं। उनमें से कई रिटायर हो गये हैं और जो रिटायर

हो गये हैं उनको टाटा कम्पनी ने पांच हजार, सात हजार की नौकरी पर रख दिया है, वे सरकमस्टेंशियल एविडेंस के नमूने हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके समने रखना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा था। एक नेशनलाइज्ड बैंक के एक्जाक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह बात अखबारों में भी निकली है और इंक्वायरी भी हुई है और जहां तक मेरी जानकारी है, इंक्वायरी में उनको भ्रष्ट पाया गया। उनकी भी अनुमति नहीं मिली। रिजर्व बैंक, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री की अनुमति में इतना समय लग जाता है कि इसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है। उनको पता है कि मुझे जाना है, इसलिये जितना बटोर सकते हैं उतना बटोर रहे हैं। तीसरा उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि बिहार के एक कलेक्टर हैं जिनके यहां छापा मारा गया था और यह बात अखबारों में भी छपी थी, उनके यहां 25 लाख की संपत्ति मिली थी। इस घटना को साल हो गया है, लेकिन अभी तक निस्तार नहीं पाया है। कुछ चीजें ऐसी हैं उनके लिये समयबद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। जो करप्ट अधिकारी है उनके बारे में वाईट पेपर पब्लिश होना चाहिये और दूसरे सोशियल कांसिएंसनेस जागृत की जानी चाहिये। मैंने कितने ही सरकारी अधिकारियों की शादी-विवाह में देखा है कि 10 लाख, 5 लाख रुपये खर्च कर दिये जाते हैं वहां पर जो प्रजेंट्स आते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इन समारोहों में मंत्री भी जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे एक परिचित थे, उनकी लड़की की शादी होनी थी। वर के लिये एक प्राइवेट कम्पनी का इंजीनियर आया जिसको तनख्वाह 900 रु. थी और दूसरा बिहार इरीगेशन विभाग में था जिसकी स्टार्टिंग 400 रु. थी। तो बूढ़ी दादी कहती है कि इरीगेशन वाले से शादी करो क्योंकि वहां पर ऊपर की आमदनी है। यह जो बड़ी बूढ़ी के चूल्हें में भ्रष्टाचार चला गया है उसको हमें बदलना है। इस लिये सिर्फ लीपापोती से काम नहीं चलेगा, आपको एक सोशियल कांसेंस भी पैदा करनी होगी। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि जो उदाहरण मैंने दिये है उनके बारे में आप जल्दी कार्यवाही करेंगे। इतना कहकर मैं इस भ्रष्टाचार विरोधी बिल का स्वागत करता हूं।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Madam, my point is very simple. There is no question of opposing this Bill. This Bill is meant for prevention of corruption amongst the public servants. But the point is that I have moved a motion for referring it to the Select Committee. Madam, the reason is that the Government which has brought forward this Bill for passing in Parliament, it will not be effective regarding those against whom serious charges of corruption have been brought in the highest echelons of the Government. I feel that by passing this Bill only some small fries at the lowest level can be caught but the corruption as such cannot be fought by this Bill. Madam, I propose that this Bill be referred to the Joint Select Committee. I have†

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. Please sit down: It will not go on record. Your speech will not go on record. Your amendment has been voted and negatived. I thought you were going to make some other point.

श्री सन्तोष बागडोदिया (राजस्थान): महोदया मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं श्री राम अवधेश सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मन से बहुत अच्छी बात भी कही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के एक एक्स-पी. ए. ने बहुत बड़ा घपला किया है। वह ट्रेजरी से रिसीट ले गया है। उसके लिये भी मंत्री महोदय को कुछ करना चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

†Not recorded.